



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2006/फाल्गुन 19, 1927

No. 32]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2006/PHALGUNA 19, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2006

सं. 6-1/2006-बी एण्ड सीएस.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा 1 (बी) के खण्ड (iv), (vii) और (viii) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

- (i) यह विनियम "अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 (2006 का 3)" कहा जाएगा।
- (ii) यह विनियम इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से लागू होगा।

2. "अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004" (2004 का 15) में विनियम 5 के वर्तमान शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा:

### **5. ब्राडकास्टों द्वारा किए जाने वाले अन्तरसंयोजन करारों का पंजीकरण**

3. "अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004" (2004 का 15) में विनियम 5 के बाद निम्नलिखित नया विनियम तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां, विनियम 5-क के रूप में जोड़ी जाएंगी:

#### **5-क. डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले अन्तरसंयोजन करारों का पंजीकरण**

- (क) सभी डायरेक्ट टु होम (डीटीएच) ऑपरेटर, उनके द्वारा ब्राडकास्टों के साथ किए गए अन्तरसंयोजन करारों तथा उनमें बाद में किए जाने वाले आशोधनों/संशोधनों को खण्ड 5-क (ख) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण के पास पंजीकृत करेंगे।
- (ख) अन्तरसंयोजन करार तथा उसमें किए जाने वाले आशोधनों/संशोधनों को पंजीकृत करने की समय-सीमा होगी:

#### **(1) वर्तमान डीटीएच ऑपरेटरों के लिए पहली संसूचना (रिपोर्टिंग)**

इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व किए गए सभी अन्तरसंयोजन करारों के लिए 30 अप्रैल, 2006, इसमें 31 मार्च, 2006 तक किए गए संशोधन तथा आशोधन भी शामिल हैं।

#### **(2) नए डीटीएच ऑपरेटरों के लिए पहली संसूचना (रिपोर्टिंग)**

अन्तरसंयोजन करारों पर हस्ताक्षर होने से 30 दिन,

### (3) तिमाही आधार पर अद्यतन करना

जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर तथा अक्टूबर से दिसम्बर के पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान किए गए अन्तरसंयोजन करारों तथा सभी अन्तरसंयोजना करारों में किए गए आशोधनों/संशोधनों के लिए कलेण्डर वर्ष के क्रमशः 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर तथा 31 जनवरी अथवा इस विनियम के विनियम 6-क के दूसरे प्रावधान के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार।”

4. “अन्तरसंयोजन करार रजिस्टर (ब्राडकास्टिंग तथा केबल सेवाएं) विनियम, 2004” (2004 का 15) में विनियम 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों, के बाद निम्नलिखित नए विनियम तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों, को विनियम 6-क के रूप में जोड़ा जाए:

“6-क. डायरेक्ट टु होम ऑपरेटर प्राधिकरण को सभी अनुबंधों सहित प्रत्येक ऐसे करार/संविदा/समझौता ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा जो ब्राडकास्टर के साथ किया गया हो तथा जिसमें संविदा/करार/समझौता ज्ञापन की सभी पार्टियों के हस्ताक्षर हों तथा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संविदा करने वाले पार्टियों का पूरा पता, संविदा संख्या, संविदा करने की तारीख, संविदा प्रारंभ करने की तारीख तथा संविदा समाप्ति की तारीख, सब्सक्राइबरों की संख्या जिसमें न्यूनतम सब्सक्राइबर गारंटी, यदि कोई हो, चैनल (चैनलों)/चैनल समूह (समूहों) की संख्या, प्रत्येक अलग-अलग चैनल (चैनलों)/चैनल समूह (समूहों) की कीमत का ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

प्राधिकरण इस विनियम के खण्ड 3 में यथा उल्लिखित रजिस्टर रखने के लिए समय-समय पर करार/संविदा/समझौता ज्ञापन के ऐसे भागों के संबंध में अलग-अलग सूचना प्राप्त करने के लिए भी फार्मेट निर्धारित कर सकता है।

प्राधिकरण समय-समय पर डाटा अथवा सूचना दायर करने के तरीके, इसे दायर करने के फार्म तथा फार्मेट, दायर की जाने वाली प्रतियों की संख्या तथा

अन्तरसंयोजन करारों के ब्यौरे दायर करने से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं तथा उससे सम्बद्ध मुद्दों के बारे में कोई अन्य शर्त भी विनिर्दिष्ट कर सकता है।”

5. इस विनियम के अनुबंध 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है जिसमें उपर्युक्त संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार,

राकेश कक्कड़, कार्यवाहक सचिव एवं सलाहकार (बी एण्ड सीएस.)

[विज्ञापन III/IV/असा./142/05]

अनुबंध—'क'

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

ट्राई ने ब्राडकास्टरों द्वारा सेवा प्रदाताओं के साथ विभिन्न प्लेटफार्मों के अन्तर्गत किए गए अन्तरसंयोजन करारों को दायर करने तथा उन्हें पंजीकृत करने के संबंध में अलग में विनियम जारी किए हैं। टीवी चैनलों के ब्राडकास्टिंग तथा वितरण से संबंधित मुद्दों पर ट्राई के विस्तृत सिफारिशों के तर्ज पर उपर्युक्त विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 5 में यह कहा गया था कि एमएसओ और एलसीओ के बीच में किए जाने वाले करार प्राधिकृत अधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाएंगे। अन्तरसंयोजन करारों को दायर करने, दायर करने के फार्मेट आदि में प्रक्रियात्मक लचीलापन लाने के लिए बाद में 2 दिसम्बर, 2005 को इस विनियम में संशोधन किया गया।

2. ऐसे कुछ विकासात्मक कार्य हुए हैं जिनमें ऐसी संभावना लग रही है कि अगले 6-9 माह में और अधिक ऑपरेटरों के पास डीटीएच प्लेटफार्म होगा। इसके अलावा, डेलिवरी के डीटीएच प्लेटफार्म के संदर्भ में केबल के माध्यम से डेलिवरी के लिए लागू करारों के ब्यौरों में भी परिवर्तन करना अपेक्षित होगा। इसलिए बेहतर निगरानी रखने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि यह प्रावधान किया जाए कि डीटीएच ऑपरेटर भी अन्तरसंयोजन करारों को दायर करें। चूंकि केबल की भांति डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा किए जाने वाले करारों की संख्या भारी नहीं होगी इसलिए अलग-अलग करारों की प्रतियां दायर की जा सकती हैं। इससे अलग-अलग करारों की भाग 'ख' में तालिका के रूप में सूचना दायर करने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। दायर करने की यह व्यवस्था ब्राडकास्टर और एमएसओ/एलसीओ के बीच हुए करारों से इस हद तक अलग है।

3. खण्ड 1 (iii) के साथ पठित ब्राडकास्टर की परिभाषा में ब्राडकास्टर अथवा उसकी वितरण एजेंसी द्वारा डीटीएच ऑपरेटर के साथ संपूर्ण भारत में किए गए अन्तरसंयोजन करार शामिल किए जाएंगे। वर्तमान विनियम का ऑपरेटिंग खण्ड 5 (क) इसे दायर करना ब्राडकास्टरों तक सीमित करता है और इससे ऐसे ब्राडकास्टरों द्वारा किए जाने वाले करार प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है जो इसका पालन इस आधार पर नहीं करते हैं कि वे देश के बाहर से आपरेट कर रहे हैं तथा इसलिए वे भारतीय कानून से शासित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह वांछनीय होगा कि डीटीएच ऑपरेटर द्वारा ब्राडकास्टरों के साथ किए जाने वाली अन्तरसंयोजन करार भी ट्राई में दायर करना जरूरी किया जाए। एमएसओ की तरह डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है इसी कारण ट्राई ने एमएसओ तथा एलसीओ के बीच किए जाने वाले करारों को प्राधिकृत अधिकारी के पास दायर कराने का निर्णय लिया है।

4. अतः प्राधिकरण ने विनिश्चय किया है कि अन्तरसंयोजन करार विनियम (2004 का 15) में संशोधन किया जाए और यह व्यवस्था की जाए कि डीटीएच सेवा प्रदाता भी उनके द्वारा ब्राडकास्टर के साथ किए गए अन्तरसंयोजन करारों को प्राधिकरण के पास दायर करें। वर्तमान विनियम में दो खण्ड 5-क तथा 6-क जोड़े जा रहे हैं।

5. डीटीएच ऑपरेटर के साथ जाने वाले उनके अन्तरसंयोजन करारों को दायर करने के लिए यह ऊपर उल्लिखित 31 दिसम्बर के विनियम के अनुसार ब्राडकास्टरों के ऊपर डाले गए मौजूदा दायित्वों के अतिरिक्त व्यवस्था है। डायरेक्ट टू होम ऑपरेटरों द्वारा दायर करने के लिए यह संशोधन बेहतर निगरानी व्यवस्था करने तथा डीटीएच प्लेटफॉर्म में संबंधित विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया है। प्राधिकरण, संशोधन विनियम अधिसूचित कर दिए जाने के बाद डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर द्वारा अपनाए जाने वाली कार्यविधि अलग से विनिर्दिष्ट करेगा।

718 87/2006-2

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2006

**No. 6-1/2006-B & CS.**—In exercise of the powers conferred upon it under Section 36 read with clauses (iv), (vii) and (viii) of Sub-section 1(b) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India makes the following regulation, namely:—

**1. Short title, extent and commencement**

- (i) This regulation shall be called “The Register of Interconnect Agreement (Broadcasting and Cable Services) (Third Amendment) Regulation, 2006 (3 of 2006).”
- (ii) This regulation shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In “The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting & Cable Services) Regulation, 2004” (15 of 2004) in place of the existing heading of regulation 5 and entries relating thereto, the following heading shall be substituted:-

**“5. Registration of interconnect agreements by broadcasters”.**

3. In “The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting & Cable Services) Regulation, 2004” (15 of 2004), after regulation 5, the following new regulation shall be inserted as regulation 5-A:-

**“5-A. Registration of interconnect agreements by Direct to Home (DTH) operators**

- (a) All direct to home operators shall register with the Authority interconnect agreements entered into by them with broadcasters as well as subsequent modifications/amendments thereto, within the time frame specified under clause 5-A(b).
- (b) The time limit for registering the interconnect agreement and amendments/modifications thereto shall be:

**(1) First Reporting for existing DTH operators**

30<sup>th</sup> April 2006 for all interconnect agreements, which had been entered into prior to the date of this notification, including amendments and modifications made upto March 31, 2006.

**(2) First Reporting for new DTH operators**

Thirty days from the signing of the interconnect agreements.

## (3) Quarterly Updation

30<sup>th</sup> April, 31<sup>st</sup> July, 31<sup>st</sup> October and 31<sup>st</sup> January of the calendar year for the modifications/amendments made in all interconnect agreements as well as new interconnect agreements during the preceding quarter of January to March, April to June, July to September and October to December, respectively or as may be specified from time to time in terms of the 2<sup>nd</sup> proviso to regulation 6-A of this regulation.”

4. In “The Register of Interconnect Agreements (Broadcasting & Cable Services) Regulation, 2004” (15 of 2004), after regulation 6 and entries relating thereto, the following new regulation and entries relating thereto shall be inserted as regulation 6-A:

“6-A. The direct to home operator shall furnish to the Authority, a duly authenticated copy of each of the agreement/contract/memorandum of understanding entered into with the broadcaster signed by the parties to the contract/agreement/Memorandum of Understanding with all its annexures containing, inter alia, the full addresses of the parties to the contract, contract number, date of entering into the contract, dates of commencement and expiry of the contract, number of subscribers including minimum subscriber guarantee, if any, number and details of names of channel(s)/ bouquet(s), price(s) of each individual channel(s)/bouquet(s)

Provided that the Authority may, from time to time, prescribe formats for seeking disaggregated information on such parts of agreement/contract/memorandum of understanding, as may be necessary, for maintaining the register as provided in clause 3 of this regulation.

Provided further that the Authority may from time to time specify the requirements, in regard to the manner of filing of data or information, the form or formats of filing, the number of copies to be filed, and other procedural aspects connected and incidental to the filing of information on interconnect agreements.”

5. This regulation contains an Explanatory Memorandum at Annex A that explains the reasons for the above amendments.

By Order,

RAKESH KACKER, Acting Secy.-cum-Advisor (B & CS)

[ADVT. III/IV/Exty./142/05]

Annex A

EXPLANATORY MEMORANDUM

TRAI issued separate regulations on 31.12.2004 for filing and registration of interconnect agreements entered into by broadcasters with service providers under different platforms. In line with the detailed recommendations of TRAI on Issues relating to broadcasting and distribution of TV channels it was stated in para 5 of the explanatory memorandum to the above regulation that the agreements entered into by between MSO and LCO shall be registered with the Authorized officers. Subsequently on 2<sup>nd</sup> December 2005 these regulations were amended to facilitate to provide flexibility in adopting procedures as regard to the manner of filing, formats of filing etc of the interconnect agreements.

2. There have been developments, which point to the likelihood of the DTH platform having more operators in the next 6-9 months. Further the details of agreements as applicable to the delivery through the cable medium would also require changes with reference to DTH platform of delivery. Therefore a provision making the DTH operator to also file the interconnect agreements is considered necessary from the point of view of better monitoring. Since the number of agreements that would be entered into by a DTH operator with the broadcaster will not be voluminous as in the case of cable it should be possible to provide for filing of copies of individual agreements. This would also obviate the need to require filing of information in tabular form in Part B, the details of individual agreements. To this extent the filing requirements would be different to that of agreements entered into between broadcaster and MSO/LCO.

3. The definition of broadcaster read with the clause 1(iii) would cover even interconnect agreements entered into by a broadcaster or its distribution agencies with DTH operator throughout the territory of India. The operating clause 5(a) of the existing regulation limits the filing to broadcasters only and this could pose difficulties in roping in the agreements entered into by broadcasters who may avoid compliance on the ground that they are operating from outside the country and therefore not governed by Indian laws. In such an event it would be desirable to make the DTH operator also file the interconnect agreements entered with the broadcasters with TRAI. Unlike the MSOs the number of DTH operators is not expected to be large, the reason why TRAI decided to make the agreements between MSOs and LCOs to be filed with the Authorized officer.

4. It has therefore been decided by the Authority to amend the Register of Interconnect Agreement Regulation (15 of 2004) by requiring the DTH service provider also to file interconnect agreements entered into with the broadcaster with the Authority. Two clauses namely, clause 5A and 6A are being added to the existing regulation.

5. This would be besides the existing obligation placed on the broadcasters, in terms of the 31st December regulation referred to above, to file their interconnect agreements entered with a DTH operator. The amendment to provide for filing by the Direct to Home operator has been done to facilitate better monitoring and to provide for specific informational requirements relevant to DTH platform. The Authority would separately be specifying the procedure to be adopted by the Direct to Home Operator for the filing(s) due after amended regulations are notified.